भारत सरकार
रेल मंत्रालय

लोक सभा
11.03.2026 के
अतारांकित प्रश्न सं. 3086 का उत्तर

फतेहगढ़ साहिब लोक सभा निर्वाचन क्षेत्र में रेल अवसंरचना संबंधी परियोजनाएं

3086. डॉ. अमर सिंह:

क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार फतेहगढ़ साहिब लोक सभा निर्वाचन क्षेत्र में स्वीकृत रेल अवसंरचना संबंधी परियोजनाओं के निष्पादन में हो रहे विलंब से अवगत है, जिसमें मार्च 2024 में स्वीकृत दोराहा रेलवे ओवरब्रिज भी शामिल है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ख) स्वीकृति के बावजूद उक्त ओवरब्रिज पर कार्य शुरू न होने के क्या कारण हैं और निर्माण कार्य कब तक शुरू होने तथा पूरा होने का प्रस्ताव है;

(ग) क्या सरकार ने उक्त परियोजनाओं के पूरा होने में विलंब के कारण आम जनता को होने वाली असुविधा और सुरक्षा जोखिमों का आकलन किया है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(घ) गत पांच वर्षों के दौरान उक्त निर्वाचन क्षेत्र में रेल अवसंरचना और यात्री सुविधाओं के लिए कितनी निधि स्वीकृत, जारी और उपयोग की गई है; और

(ङ) सरकार द्वारा उक्त क्षेत्र में लंबित रेल परियोजनाओं में तेजी लाने और यात्री सुरक्षा तथा संपर्क में सुधार के लिए क्या कदम उठाए गए हैं या उठाए जा रहे हैं?

उत्तर

रेल, सूचना और प्रसारण एवं इलेक्ट्रॉनिकी और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री
(श्री अश्विनी वैष्णव)

(क) से (ङ): भारतीय रेल में समपारों के स्थान पर ऊपरी/निचले सड़क पुलों के निर्माण के प्रस्तावों की स्वीकृति एक सतत और गतिशील प्रक्रिया है। ऐसे कार्यों की प्राथमिकता निर्धारण और उन्हें शुरू

करने का कार्य रेल परिचालन में संरक्षा, रेलगाड़ियों की गतिशीलता तथा सड़क उपयोगकर्ताओं पर इसके प्रभाव और व्यवहार्यता के आधार पर किया जाता है।

2004-14 की तुलना में 2014-26 (जनवरी 2026 तक) की अवधि के दौरान भारतीय रेल में निर्मित ऊपरी/निचले सड़क पुलों की संख्या निम्नानुसार है:-

अवधि	निर्मित ऊपरी/निचले सड़क पुल
2004-14	4,148 अदद
2014-26 (अक्टूबर, 2026 तक)	14,024 अदद (पंजाब राज्य में 434 अदद सहित)

01.02.2026 की स्थिति के अनुसार, भारतीय रेल में 1,14,196 करोड़ रु. की लागत से 4,802 अदद ऊपरी/निचले सड़क पुल स्वीकृत किए गए हैं, जिसमें पंजाब राज्य में 120 अदद ऊपरी/निचले सड़क पुल शामिल हैं, जिनकी लागत 1,848 करोड़ रुपए है जो योजना और क्रियान्वयन के विभिन्न चरणों में हैं। इनमें से, फतेहगढ़ साहिब लोक सभा संसदीय निर्वाचन-क्षेत्र में 04 अदद ऊपरी/निचले सड़क पुल कार्य को 56 करोड़ रु. की लागत पर स्वीकृत किया गया है।

किलोमीटर 353/990 पर समपार सं. 164 ए-बी के स्थान पर ऊपरी सड़क पुल का कार्य आरंभ में 2013 में पंजाब सरकार के साथ लागत में भागीदारी के आधार पर शुरू किया गया था। राज्य सरकार द्वारा कार्य का निष्पादन किया जाना था। बहरहाल, राज्य सरकार द्वारा कार्य के निष्पादन में अक्षमता के कारण 2021 में कार्य को रोक दिया गया था।

सार्वजनिक मांग को ध्यान में रखते हुए, इस कार्य को फरवरी, 2024 में रेलवे की लागत पर पुनः स्वीकृत किया गया था। कार्य के लिए सामान्य व्यवस्था आरेखण को अनुमोदन दिया गया है और रेलवे द्वारा ठेका सौंप दिया गया है। निर्माण कार्य शुरू कर दिया गया है।

रेलवे ने ऊपरी/निचले सड़क पुलों के निर्माण-कार्यों की प्रगति में तेजी लाने के लिए निम्नलिखित उपाय किए हैं:

i. सुचारू निष्पादन सुनिश्चित करने के लिए सामान्य व्यवस्था आरेख को अंतिम रूप देने से पहले संबंधित राज्य सरकार/सड़क स्वामित्व प्राधिकरण के साथ संयुक्त सर्वेक्षण किया जाता है।

ii. ऊपरी सड़क पुल/निचले सड़क पुल कार्यों से संबंधित विभिन्न मुद्दों के समाधान के लिए रेलवे और राज्य सरकार के अधिकारियों की आवधिक बैठकें आयोजित की जाती हैं।

iii. डिजाइन अनुमोदन के दौरान देरी से बचने के लिए रेलवे के हिस्से पर सड़क के स्पैन, तिरछापन और चौड़ाई के विभिन्न संयोजनों के लिए अधिरचना रेखाचित्रों का मानकीकरण किया गया है। इसे एक सार-संग्रह के रूप में जारी किया गया है, जिसे शीघ्र नियोजन के लिए रेल लाइनों पर ऊपरी सड़क पुल के लिए सीधे अपनाया जा सकता है।

iv. रेलवे द्वारा ऊपरी सड़क पुल/निचले सड़क पुल कार्यों को जहाँ-कहीं संभव होता है एकल इकाई के आधार पर निष्पादित करने की योजना बनाई जाती है। यदि कोई सड़क स्वामित्व प्राधिकरण/राज्य सरकार चाहे, तो रेलवे उन्हें एकल इकाई के आधार पर कार्य निष्पादित करने की अनुमति दे सकता है।

पंजाब

पंजाब राज्य में पूर्णत:/अंशत: तौर पर आने वाली अवसंरचना परियोजनाओं और संरक्षा कार्यों के लिए किया गया बजट आवंटन निम्नानुसार है:

अवधि	परिव्यय
2009-14	225 करोड़ रुपए/वर्ष
2025-26	5,421 करोड़ रुपए (24 गुना से अधिक)

01.04.2025 की स्थिति के अनुसार, पंजाब राज्य में पूर्णतः/अंशतः तौर पर आने वाली 21,926 करोड़ रु. की लागत वाली कुल 714 कि.मी. लंबाई की 09 परियोजनाएँ (04 नई लाइन और 05 दोहरीकरण) योजना/स्वीकृति/क्रियान्वयन के विभिन्न चरणों में हैं, जिनमें से 115 कि.मी. की लंबाई को कमीशन किया जा चुका है और मार्च, 2025 तक 8,079 करोड़ रुपए व्यय किए जा चुके हैं। सार इस प्रकार है:-

कोटि	परियोजनाओं की संख्या	कुल लंबाई	कमीशन की गई लंबाई	मार्च, 2025 तक व्यय (करोड़ रुपए में)
नई लाइन	04	252 किमी	64 किमी	7,359
दोहरीकरण/मल्टी ट्रैकिंग	05	462 किमी	51 किमी	720
कुल	09	714 किमी	115 किमी	8,079

पंजाब राज्य में पूर्णत:/अंशत: तौर पर आने वाली हाल ही में पूरी की गईं कुछ परियोजनाओं का विवरण निम्नानुसार है:

क्र. सं.	परियोजना	लागत (करोड़ रुपए में)
1	चक्की बैंक-भरौली दोहरीकरण (3 कि.मी.)	15
2	जाखल-मानसा दोहरीकरण (45 कि.मी.)	163
3	मीरथल-भंगाला ब्यास नदी दोहरीकरण (2.5 कि.मी.)	74
4	अंबाला-धप्पर-चंडीगढ़ दोहरीकरण (45 कि.मी.)	339
5	मानसा - बठिंडा दोहरीकरण (49 कि.मी.)	216
6	अमृतसर-छहरटा दोहरीकरण (7 कि.मी.)	31
7	जालंधर-पठानकोट-जम्मू तवी दोहरीकरण (209 कि.मी.)	850
8	कठुआ-माधोपुर पंजाब - रावी पुल पर दोहरीकरण (2.5 कि.मी.) सहित	257
9	राजपुरा-बठिंडा दोहरीकरण (173 कि.मी.)	2459

पंजाब राज्य में पूर्णत:/अंशतः तौर पर आने वाली कुछ परियोजनाएं जिन्हें शुरू किया गया हैं, निम्नानुसार हैं:

क्र. सं.	परियोजना	लागत (करोड़ रुपए में)
1.	नंगल डैम-तलवाड़ा और मुकेरियां-तलवाड़ा नई लाइन (123 कि.मी.)	2018

2.	भानुपल्ली-बिलासपुर-बेरी नई लाइन (63 किमी)	6753
3.	कादियां-ब्यास नई लाइन (40 किमी)	842
4.	फिरोजपुर-पट्टी नई लाइन (26 किमी)	300
5.	तलवंडी साबो के रास्ते रामा मंडी (रमन)-मौर मंडी (मौर) (29 किमी) नई लाइन	154
6.	लुधियाना-किला रायपुर दोहरीकरण (19 किमी)	238
7.	लुधियाना-मुल्लनपुर दोहरीकरण (21 किमी)	235
8.	राजपुरा-मोहाली नई लाइन (18 किमी)	443
9.	राजपुरा बाईपास लाइन (14 किमी)	412

भारत सरकार परियोजनाओं को पूरा करने के लिए तैयार है, हालांकि इसकी सफलता पंजाब सरकार के सहयोग पर निर्भर है। उदाहरण के लिए, कुछ प्रमुख परियोजनाएं जो भूमि अधिग्रहण के कारण विलंबित हैं, का ब्यौरा निम्नानुसार है: -

क्र.सं.	परियोजना का नाम	कुल अपेक्षित भूमि (हेक्टेयर में)	कुल अधिगृहीत भूमि (हेक्टेयर में)	अधिगृहीत की जाने वाली शेष भूमि (हेक्टेयर में)
1.	फिरोजपुर पट्टी नई लाइन	166	0	166
2.	अलाल-हिम्मताना कॉर्ड लाइन	20	0	20
3.	कादियां-ब्यास नई लाइन	151	0	151
4.	रामा मंडी (रमन) - तलबंडी साबो नई लाइन	85	0	85

फिरोजपुर-पट्टी नई लाइन (26 किमी) अंतर्राष्ट्रीय सीमा के पास एक महत्वपूर्ण परियोजना है जो पूर्ण रूप से पंजाब में है। इस परियोजना के लिए भूमि पंजाब राज्य सरकार द्वारा निशुल्कः सौंपी

जानी थी। फिरोजपुर और तरनतारन जिलों में कुल 166 हेक्टेयर भूमि अधिगृहीत की जानी है। पूरी भूमि के लिए अधिनिर्णय मार्च-23 में प्रकाशित किया जा चुका है। बहरहाल अधिनिर्णित राशि का संवितरण राज्य सरकार द्वारा नहीं किया गया है। इस महत्वपूर्ण सीमा क्षेत्र परियोजना के क्रियान्वयन में देरी को ध्यान में रखते हुए, रेल मंत्रालय ने अपनी स्वयं की वित्तपोषण से फिरोजपुर-पट्टी नई लाइन (26 किमी) को शुरू करने का निर्णय लिया है।

कादियां-ब्यास (39.6 किमी) नई रेल लाइन परियोजना 2011-12 में 205 करोड़ रु. की लागत पर स्वीकृत की गई थी। बहरहाल, कानून एवं व्यवस्था मुद्दों के कारण परियोजना को आगे नहीं बढ़ाया जा सका था। परियोजना को रोक दिया गया था। बहरहाल, इस परियोजना के महत्व को देखते हुए, कार्य पुनः शुरू करने का निर्णय लिया गया है।

राजपुरा-मोहाली नई लाइन परियोजना (18 किमी) फतेहगढ़ साहिब संसदीय क्षेत्र से होकर गुजरती है जिसे हाल ही में 443 करोड़ रु. की लागत पर स्वीकृत किया गया है। इस परियोजना को विशेष रेल परियोजना घोषित किया जा चुका है। नवंबर 2025 में भूमि अधिग्रहण सक्षम प्राधिकारी को भी नामांकित किया गया है और भूमि अधिग्रहण कार्य शुरू कर दिया गया है। यह परियोजना अंबाला का परिहार करते हुए, सरहिंद-गोबिंदगढ़ और राजपुरा क्षेत्र के बीच दक्षिण पंजाब (बठिंडा क्षेत्र) को सीधा चंडीगढ़ से जोड़ेगी।

ऊपरी/निचले सड़क पुल सहित रेल परियोजनाओं का पूरा होना विभिन्न कारकों पर निर्भर करता है, जो निम्नानुसार शामिल हैं:

- राज्य सरकार द्वारा भूमि अधिग्रहण
- वानिकी स्वीकृति
- अतिलंघकारी जनोपयोगी सेवाओं का स्थानांतरण
- विभिन्न प्राधिकरणों से सांविधिक स्वीकृतियां
- क्षेत्र की भू-वैज्ञानिक और स्थलाकृतिक परिस्थितियां
- परियोजना स्थल के क्षेत्र में कानून एवं व्यवस्था की स्थिति
- परियोजना स्थल विशेष के लिए एक वर्ष में कार्य करने के महीनों की संख्या आदि

ये सभी कारक परियोजना/परियोजनाओं के समापन समय और लागत को प्रभावित करते हैं।

स्टेशन पुनर्विकासः

रेल मंत्रालय ने अमृत भारत स्टेशन योजना दीर्घकालिक दृष्टिकोण के साथ स्टेशनों के पुनर्विकास के लिए योजना शुरू की है।

इस योजना में स्टेशनों को बेहतर बनाने के लिए मास्टर प्लान तैयार करना और चरणबद्ध तरीके से उनका क्रियान्वयन करना शामिल है। मास्टर प्लानिंग में निम्नलिखित शामिल हैं:

- स्टेशन और परिचलन क्षेत्रों तक पहुँच में सुधार
- शहर के दोनों ओर स्टेशन का एकीकरण
- स्टेशन भवन में सुधार
- प्रतीक्षालय, शौचालय, बैठने की व्यवस्था और पेयजल-बूथों में सुधार
- यात्री यातायात के अनुरूप चौड़े पैदल पार पुल/एयर कॉन्कोर्स का प्रावधान
- लिफ्ट/एस्केलेटर/रैंप का प्रावधान
- प्लेटफ़ॉर्म की सतह में सुधार/प्रावधान और प्लेटफ़ॉर्म को ऊपर से कवर करना
- 'एक स्टेशन एक उत्पाद' जैसी योजनाओं के जरिए स्थानीय उत्पादों के लिए कियोस्क का प्रावधान
- पार्किंग क्षेत्र, मल्टीमोडल एकीकरण
- दिव्यांगजनों के लिए सुविधाएँ
- बेहतर यात्री सूचना प्रणाली
- प्रत्येक स्टेशन पर आवश्यकता को ध्यान में रखते हुए एग्जीक्यूटीव लाउंज, व्यावसायिक बैठकों के लिए निर्दिष्ट स्थान, भूसुदर्शनीकरण आदि का प्रावधान।

इस योजना में आवश्यकतानुसार, चरणबद्ध एवं व्यवहार्य रूप से दीर्घकालिक और पर्यावरण अनुकूल समाधान, गिट्टी रहित पटरियों की व्यवस्था आदि और दीर्घावधि में स्टेशन पर सिटी सेन्टरों के निर्माण की भी परिकल्पना की गई है।

अभी तक, इस योजना के अंतर्गत विकसित करने हेतु 1337 स्टेशनों को चिह्नित किया गया है, जिनमें से फतेहगढ़ साहिब लोक सभा संसदीय क्षेत्र के सरहिंद स्टेशन सहित 30 स्टेशन पंजाब राज्य में स्थित हैं। पंजाब राज्य में अमृत भारत स्टेशन योजना के अंतर्गत विकसित करने हेतु चिह्नित स्टेशनों के नाम निम्नानुसार हैं:

राज्य	स्टेशनों की संख्या	स्टेशनों के नाम
पंजाब	30	अबोहर, अमृतसर, आनंदपुर साहिब, ब्यास, बठिंडा जंक्शन, ढंडारी कलां, धुरी, फाजिल्का, फिरोजपुर कैंट, गुरदासपुर, होशियारपुर, जालंधर कैंट जंक्शन, जालंधर सिटी जंक्शन, कपूरथला, कोटकपुरा जंक्शन, लुधियाना जंक्शन, मालेरकोटला, मानसा, मोगा, मुक्तसर, नांगल डैम, पठानकोट कैंट, पठानकोट जंक्शन, पटियाला, फगवाड़ा जंक्शन, फिल्लौर जंक्शन, रूप नगर, साहिबजादा अजीत सिंह नगर मोहाली, संगरूर, सरहिंद

पंजाब राज्य में अमृत भारत स्टेशन योजना के तहत रेलवे स्टेशनों पर विकास कार्य अच्छी गति से शुरू किए गए हैं। अब तक पंजाब में 3 स्टेशनों (आंनदपुर साहिब, मुक्तसर और साहिबजादा अजीत सिंह नगर मोहाली) के कार्य इस योजना के अंतर्गत पूरे किए गए हैं।

अन्य स्टेशनों पर विकास कार्यों की गतिविधियां अच्छी गति में शुरू किए गए है और कुछ स्टेशनों की प्रगति निम्नानुसार हैः-

सरहिंद स्टेशन: स्टेशन भवन में सुधार, प्रवेश प्रांगण, शौचालय सुविधा के साथ वातानुकूलित प्रतीक्षालय, द्वितीय श्रेणी प्रतीक्षालय में सुधार, शौचालय ब्लॉक, परिचलन क्षेत्र, पार्किंग, प्रवेश/निकास गेट, प्रकाश और संसूचक पूरा कर लिया गया है। लिफ्ट का कार्य और 12 मी. फुट ओवर ब्रिज का कार्य शुरू किया गया है।

गुरदासपुर स्टेशनः स्टेशन भवन, प्लेटफ़ॉर्म शेल्टर, प्लेटफ़ॉर्म की सतह में सुधार, प्रतीक्षालय, शौचालय, परिचलन क्षेत्र, प्रांगण और प्रकाश व्यवस्था का कार्य पूरा कर लिया गया है। नए

प्लेटफार्म नं. 2, बुकिंग एवं प्रतीक्षालय, परिचलन क्षेत्र, पार्किंग, मुख्य प्रवेश और दूसरी ओर प्रवेश/निकास गेट और 12 मी. फुट ओवर ब्रिज का कार्य शुरू किया गया है।

पटियाला स्टेशनः स्टेशन भवन, प्रवेश प्रांगण, प्लेटफार्म शेल्टर, प्रतीक्षालय, विश्रामालय, शौचालय, परिचलन क्षेत्र, पार्किंग, प्रवेश/निकास गेट और संसूचक का सुधार कार्य पूरा किया गया है। प्लेटफार्म की सतह, दूसरे प्रवेश द्वार का विकास, लिफ्ट और 12 मीटर फुट ओवर ब्रिज का कार्य शुरू किया गया है।

संगरूर स्टेशन: स्टेशन भवन, प्रवेश प्रांगण, प्लेटफॉर्म शेल्टर, प्रतीक्षालय, शौचालय ब्लॉक, परिचलन क्षेत्र, पार्किंग, प्रवेश/निकास गेट और संसूंचक के सुधार के कार्य पूरे किए गए हैं। प्लेटफॉर्म नं. 1 पर प्लेटफॉर्म सतहीकरण, लिफ्ट और 4.8 मीटर फुट ओवर ब्रिज का कार्य शुरू किया गया है।

भारतीय रेल पर रेलवे स्टेशनों का विकास/पुनर्विकास/उन्नयन/आधुनिकीकरण निरंतर चलने वाली सतत् प्रक्रिया है तथा इस संबंध में कार्य परस्पर प्राथमिकता और निधियों की उपलब्धता के अध्यधीन आवश्यकतानुसार किए जाते हैं। कार्यों को स्वीकृत और निष्पादित करते के समय निचली कोटि के स्टेशनों की तुलना में उच्च कोटि के स्टेशनों के विकास/पुनर्विकास/उन्नयन/आधुनिकीकरण को प्राथमिकता दी जाती है।

स्टेशनों का विकास/उन्नयन/आधुनिकीकरण, जिसमें अमृत भारत स्टेशन योजना के अंतर्गत शामिल हैं, सामान्यतः योजना शीर्ष-53 'ग्राहक सुविधाएँ' के तहत वित्तपोषित किया जाता है। योजना शीर्ष-53 के अंतर्गत आवंटन और व्यय का विवरण क्षेत्रीय रेलवे-वार रखा जाता है, न कि कार्य-वार, स्टेशन-वार, या राज्य-वार। पंजाब दो रेलवे जोनों, अर्थात् उत्तर रेलवे और उत्तर पश्चिम रेलवे के अधिकार क्षेत्र में आता है। इन जोनों को पिछले चार वर्षों और चालू वर्ष के लिए योजना शीर्ष-53 के तहत ₹8,501 करोड़ आवंटित किए गए हैं। पिछले चार वर्षों और चालू वर्ष (जनवरी 2026 तक) में इन जोनों द्वारा योजना शीर्ष-53 के अंतर्गत किए गए व्यय की राशि ₹7,310 करोड़ है।

गाड़ियां:

वर्तमान में, फतेहगढ़ साहिब स्टेशन को निम्नलिखित 8 गाड़ी सेवाओं द्वारा सेवित किया जाता है:

क्र.सं.	गाड़ी सं. और नाम
1	14053 दिल्ली - दौलतपुर चौक हिमाचल एक्सप्रेस
2	14054 दौलतपुर चौक-दिल्ली हिमाचल एक्सप्रेस
3	64514 नंगल डैम - अम्बाला कैंट मेमू
4	64515 अंबाला कैंट - नंगल डैम मेमू
5	64511 हरिद्वार - अंब अन्दौरा मेमू
6	64517 अंबाला कैंट - नंगल डैम मेमू
7	64518 नंगल डैम - अंबाला कैंट मेमू
8	64513 सहारनपुर - नंगल डैम मेमू

इसके अलावा, किसी मार्ग/रेलखंड पर नई गाड़ी सेवाएँ शुरू करना निरंतर चलने वाली प्रक्रिया है जो निम्नलिखित कारकों पर निर्भर करता है:

- **उस खंड की क्षमता,**
- **पथ की उपलब्धता,**
- **अपेक्षित चल स्टॉक की उपलब्धता,**
- **चल स्टॉक के लिए उपयुक्त अवसंरचना की उपलब्धता,**
- **रेलपथ और अन्य परिसंपत्तियों की अनुरक्षण आवश्यकता।**

******